भोजन-वन के बीच संबंध का प्रबंधन करने पर भारतीय जनजाति से सबक

मणिपद्मा जेना द्वारा

रायगढ़, भारत, 19 मई 2015 (आईपीएस) - पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य में दूर दराज़ नियमगिरी पहाड़ी शृंखला में 240 वर्ग किमी में फैला हुआ है, एक प्राचीन आदिवासी समूह जिसे डोंगरिया कोंध नाम से जाना जाता है और जिसने एक पथ प्रदर्शक के तौर पर ख्याति अर्जित की है।

एक बहुत बड़ी ब्रिटिश खनन कंपनी, जिसने इस खनिज बहुल क्षेत्र में बॉक्साइट निष्कर्षण में अरबों रुपयों का निवेश किया था, उसके साथ एक दशक लंबी चली लड़ाई लड़ने और अंत में उसे जीतने के बाद, डोंगरिया कोंध ने 2013 में दुनियाभर के लाखों आदिवासी लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया कि अभी भी उपेक्षित लोगों द्वारा ताकतवर लोगों के विरुद्ध लड़ाई जीती जा सकती है।

अब, यह स्वदेशी समूह एक बार फिर से भूख और वनों की कटाई की दोहरी समस्याओं, जिससे पूरा विश्व परेशान है, उससे लड़ने के लिए खड़ा हो गया है। ये समूह पारंपरिक तौर पर जीवन जीने का सपना देखता है बावजूद उस विनाशकारी विकास की लहर के चलते जो खेती की पारंपरिक और सतत प्रथाओं के लिए एक खतरा बनी हुई है।
इधर, एक डोंगरिया कोंध महिला बरदा पत्तों को तोड़ रही है, जो समुदाय के लिए लौह का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। श्रेय: मणिपद्मा जेना / आईपीएस

इधर, एक डोंगरिया कोंध महिला बरदा पत्तों को तोड़ रही है, जो समुदाय के लिए लौह का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। श्रेय: मणिपद्मा जेना / आईपीएस

डोंगरिया कोंध के लोग जिन की संख्या लगभग 10,000 है, वनों और पहाड़ों को पवित्र स्थल मानते हैं, और सदियों से ही भूमि के साथ सद्भाव में रहते चले आए हैं। यहाँ एक वर्ष में एक परिवार औसतन 130 किलो वन्य उपज की कटाई कर लेता है।

उनका खानपान अलग-अलग होता है, जिसमें पौधों की लगभग 25 प्रजातियां, जो सीधे वनों से प्राप्त होती हैं शामिल हैं, जबकि नियमगिरी पहाड़ियों में से निकालने वाले झरने ताज़ा, साफ पानी पूरा वर्ष प्रदान करते हैं।

किन्तु बड़े पैमाने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अंधाधुंध वनों की कटाई, साथ ही लकड़ी और कागज उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए तेज़ी से उगने वाले पेड़ों के मोनो-कल्चर वृक्षारोपण, और खनन गतिविधियों ने डोंगरिया कोंध और अन्य स्वदेशी समूहों के लिए

पिछले 30 वर्षों से अधिक के समय में खाद्य उपलब्धता को 30 प्रतिशत से ऊपर तक कम कर दिया है और उन्हें इकट्ठा करने में लगने वाले समय को 80 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।

आज, डोंगरिया कोंध समुदाय के 55 प्रतिशत व्यसकों में प्रोटीन-ऊर्जा की कमी पाई जाती है और 60 प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।

यह परिस्थिति पूरे भारत के रुझान दर्शाती है, एक ऐसा देश जिसकी 1 अरब 20 करोड़ है, जहां कुछ सबसे गरीब और भूखे लोग वनों में या उसके आसपास रहते हैं।

दुनिया के लगभग 80 करोड़ 50 लाख कुपोषित में से भारत में एक चौथाई लोग निवास करते हैं, साथ ही कम वज़न वाले बच्चों की संख्या का तिहाई हिस्सा भारत में है और इस विशाल देश की 24 करोड़ 50 लाख वाली जंगलों में रहने वाली आबादी का लगभग एक तिहाई भूख का शिकार हैं।

तथ्य की विडंबना यह है कि वे लोग जो आसानी से उपलब्ध होने वाले भोजन के स्रोतों के निकट रहते हैं वे ही भूखा रह रहे हैं और इसकी जानकारी नीति बनाने वालों को है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र वनों के भूख मिटाने और पर्यावरण में बदलाव के प्रभाव को कम करने में उनकी अहमियत के कारण उन्हें बचाने के हर संभव प्रयासों में लगा हुआ है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में।

1 अरब 60 करोड़ लोगों के साथ - जिसमें लगभग 2,000 स्वदेशी संस्कृतियाँ शामिल हैं - जो भोजन, आवास, आय और ईंधन के लिए वनों पर सीधे निर्भर करती हैं, इन्हें संरक्षण देना यूएन के सतत विकास एजेंडा से सीधे जुड़ा हुआ है, और जो 2012 में महासचिव बान की-मून द्वारा आरंभ किए गए 'ज़ीरो हंगर चैलेंज' में भी भूमिका निभा सकता है, जिसका उद्देश्य कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की इस बीमारी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है।

यह सुनने में आसान लगता है, जबकि हर वर्ष लगभग 1 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो जाती है, जिससे लाखों लोग भोजन के उनके अकेले स्रोत से वंचित रह जाते हैं।

हालांकि ये रुझान बहुत निराशाजनक लगता है, किन्तु एक वैकल्पिक आर्थिक मॉडल के तौर पर हमें नियमगिरी पहाड़ियों से सबक लेना चाहिए, जो लाभ के लिए जीते जागते पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े पैमाने पर विनाश के बजाय समुदाय प्रबंधन और नियंत्रण पर आधारित है।

यहाँ ओडिशा में, वन-भोजन के बीच संबंध और प्राचीन लोगों के संचित पारंपरिक ज्ञान का मेल हुआ है, जो एक ऐसे क्षैतिज की ओर ले जाएगा जहां कोई भी भूखा नहीं रहेगा। (समाप्त)